यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/112/2020 **दिनांक** : 06.07.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

19 जुलाई, 2020 बैंक राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ

जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि 19 जुलाई, 2020 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ है। इस विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 28/212/2020/50 दिनांक 5.7.2020 जारी किया गया है तथा इस अवसर को मनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम भी दिए गए हैं। हम इस परिपत्र का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना, संज्ञान एवं अनुपालन हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

19 जुलाई 1969 – 2020
बैंक राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ मनायें

19 जुलाई हमारे देश के बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह वो दिन था, जब वर्ष 1969 में 19 जुलाई को, 14 प्रमुख निजी बैंकों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकत किया गया था, तब से इन बैंकों ने सामाजिक अभिविन्यास के साथ एक नया रास्ता शुरू किया था।

यह दिन एआईबीईए की डायरी में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एआईबीईए ने इसे हासिल करने और निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण क लिए मांग में अग्रणी भूमिका निभाई। इस मांग को हासिल करने के लिए एआईबीईए के दृढ़ निश्चय और संघर्ष के लगभग दो दशक हमारे संगठन के विख्यात इतिहास का एक शानदार हिस्सा है।

उन दिनों, हमारे देश में सभी बैंकों का स्वामित्व शक्तिशाली औद्योगिक घरानों, व्यापारिक घरानों और पूंजीपतियों के पास था। इसलिए निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग का सभी अपेक्षित तिमाहियों, राजनीतिक और अन्यथा से कड़े प्रतिरोध के साथ सामना हुआ। इन बैंकों के मालिकों की अपनी शक्तिशाली लॉबी और स्पष्ट और समझने योग्य कारणों के लिए सरकार पर बहुत अधिक प्रभाव था।

कई लोगों ने यह कहते हुए एआईबीईए का उपहास उड़ाया कि एआईबीईए के लिए इसे हासिल करना बहुत ही बड़ा मुद्दा था। कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीतिक मांगों का उठाना श्रम संगठन का काम नहीं है और एआईबीईए के लिए यह बेहतर होगा कि वो वेतन पुनरीक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, आदि जैसी मांगों के लिए सीमित रहे। लेकिन एआईबीईए हतोत्साहित नहीं हुआ और डर महसूस नहीं किया।

जारी पृष्ठ 2

एआईबीईए को संस्थापक पिताओं के मूल दर्शन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि बैंक कर्मचारियों की बेहतरी के लिए संघर्ष करने के अलावा, एआईबीईए को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक बड़े पैमाने पर आम लोगों की मदद करें, विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा दौ सौ साल की अधीनता के बाद एक विकासशील आर्थिक परिदृश्य में।

साथी प्रभात कार और साथी एच एल परवाना, जिन्हें हम सभी एआईबीईए के वास्तुकारों के रूप में मानते हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण क लिए अभियान की अगुआई की। एआईबीईए के ध्वज तले बैंक कर्मचारियों ने शानदार प्रतिक्रिया दी। सड़कों पर, बैंक कर्मचारी अभियान और संघर्ष में थे। संसद के अंदर, साथी प्रभात कार, जो 1957 से 1967 तक सांसद रहे, ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और राजनीतिक समर्थन जुटाया।

यह मुद्दा एक लोकप्रिय मांग बन गया और 1969 में, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में, कांग्रेस पार्टी में ऊर्ध्वाधर विखंडन और विभाजन की कीमत पर, श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

एआईबीईए विजेता बन गया क्योंकि एआईबीईए ही एकमात्र संगठन था जिसने इस मुद्दे को उठाया, मांग की, आंदोलन किया और इस हेतु संघर्ष किया। इसलिए हम सभी वैध रूप से गर्व महसूस कर सकते हैं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने हमारे बैंकों का चेहरा बदल दिया है। यह पहले वर्ग बैंकिंग थी और राष्ट्रीयकरण के बाद यह सार्वजनिक बैंकिंग बन गई। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों बैंक शाखायें खोली गईं। बैंक राष्ट्रीयकरण लोगों की बचतों के लिए सुरक्षा और बचाव लाया। ऋण देने के लिए जिन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई, वे प्राथमिकता क्षेत्र बन गए। बैंकों ने कृषि, रोजगार सृजन, गरीबो उन्मूलन, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, लघु और मध्यम उद्योगों, बुनियादी ढांचे, निर्यात आदि के लिए ऋण देना शुरू किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हमारे देश के आर्थिक विकास पर बड़ा प्रभाव डालना शुरू कर दिया।

यह याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि बैंक राष्ट्रीयकरण, जिसे एआईबीईए ने हासिल किया, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के बड़े अवसर पैदा हुए और लाखों शिक्षित युवाओं को बैंकों में नौकरी मिली। 1969 में कर्मचारियों की कुल संख्या सिर्फ 1 लाख के आसपास थी और आज, बकों के राष्ट्रीयकरण के कारण, हमारे पास लगभग दस लाख बैंक कर्मचारी हैं।

राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हमारे देश के आर्थिक विकास को चलाने के लिए इंजन बन गए। हमारे बैंक गर्व से राष्ट्र निर्माण संस्थान बन गए।

लेकिन, अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण, बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के नाम पर जैसा कि आईएमएफ, विश्व बैंक आदि द्वारा आदेशित और वांछित है और जैसा कि क्रमिक सरकारों द्वारा आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केन्द्र में वर्तमान सरकार आक्रामक रूप से बैंकिंग विनियमों के निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों का अनुसरण कर रही है।

निजी कॉर्पोरेट विशाल ऋणों के चूककर्ता हैं लेकिन उन्हें सभी रियायतें दी जा रही हैं। यह बोझ आम लोगों पर डाला जाता है।

आज जब हमारा देश और हमारी अर्थव्यवस्था चौराहे पर हैं, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, उन्हें विस्तारित करने की आवश्यकता है और उन्हें एक जीवंत अर्थव्यवस्था को आकार देने में बहुत अधिक भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उनके सामाजिक अभिविन्यास को सुदृढ़ करने के बजाय, घड़ी को उलटा घुमाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह इस पृष्ठभूमि में है कि हम 19 जुलाई, 2020 को बैंक राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ का उत्सव मनायेंगे।

जबकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण को हासिल करने में एआईबीईए के गौरवशाली योगदान को याद करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, यह समान रूप से आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग की रक्षा करने और हमारे बैंकों के निजीकरण के प्रयासों को परास्त करने के लिए खुद से पुनः–प्रतिबद्ध होने क लिए इस अवसर का उपयोग किया जाये।

जारी पृष्ठ 3

हमें खतरनाक ढंग से बढ़ते खराब ऋणों/अनर्जक आस्तियों के रूप में कॉर्पोरेट लूट के खतरे ओर सजावटी छंटनी और बट्टे खातों के रूप में उनको निरंतर रियायत के विरूद्ध हमारे संघर्ष को भी सघन करना चाहिए।

हम आम लोगों की जमाराशियों/बचतों के लिए ब्याज दर बढ़ाने तथा कॉर्पोरेट खराब ऋणों के लिए विशाल प्रावधानों के कारण राजस्व के नुकसान के समायोजन के लिए सेवा शुल्कों में असामान्य वृद्धि के खिलाफ हमारी मांग को भी आगे बढ़ाना चाहिए।

सामान्य समय में, हम अवसर को मनाने के लिए पूर्ण–स्तरीय कार्यक्रम करेंगे लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जहां पूर देश और हमारे लोगों को कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य खतरे का सामना करना पड़ रहा है, और बैंक कर्मचारो कठिनाईयों के बीच बैंकों में उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए विभिन्न पाबंदो और प्रतिबंध हैं, हम निम्नलिखिम कायक्रमों को तद्नुसार करेंगे :

1. **एआईबीईए के फेसबुक पेज के माध्यम से 19 जुलाई, 2020 (रविवार) को सायं 5 बजे राष्ट्रीय वेबिनार।**
2. **बैंकों के जानबूझकर चूककर्ताओं की सूची जारी करना।**
3. **क्षेत्रीय भाषाओं में ई–पर्चो/पत्रिकाओं का प्रसारण।**
4. **शाखाओं पर पोस्टरों का प्रदर्शन।**
5. **सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से ई–पोस्टरों का प्रसारण।**
6. **प्रधानमंत्री को जन याचिका**
7. **20.7.2020 (सोमवार) को बैज धारण करना।**
8. **20 से 31 जुलाई, 2020 के बीच हमारी यूनियनों/राज्य फैडरेशनों द्वारा आभासी बैठकं/वेबिनार आदि**

प्रिय साथिया, हमारे आसपास के परिदृश्य की गंभीरता को अतिरंजित या सविस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सभी इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग पर हमले बढ़ रहे हैं। हमारे बैंकों क सामाजिक अभिविन्यास को कमजोर किया जा रहा है। निजीकरण के खतरे दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमें सावधान और जागरूक होना है।

हम अपनी सभी इकाईओं और सदस्यों से कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक लागू करने का आह्वान करते हैं। कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश फैडरेशनों को अभी से आगे बढ़ना चाहिए।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

जनता का धन जनता के कल्याण के लिए
न कि कॉर्पोरेट लूट के लिए